Permission to MNCs to set up Industries Banned in their Parent Country

2725. SHRI S. MADHAVAN:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Hindu dated the 4th February, 1995 about the approval of Government allowing multinationals to start industries which had been banned in their own countries and about the concern expressed by the former Chairman of the Space Commission; and

(b) if so, what are the details of those multinational companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHANA SAHI): (a) and (b) The New Industrial Policy 1991 lays down the guidelines for foreign technical collaboration and joint ventures. The entry of foreign investors is expected to bring attendant advantages of technology transfer, managerial and marketing expertise as also new possibilities of exports. The apprehension regarding dumping of obsolete/banned technology is not well founded as the competitive domestic market will ensure that units with obsolete technologies do not survive. Further there is no reason to believe that multi-nationals would be bringing in obsolete technology as they are now being permitted majority holdings which means that they would be controlling the industry themselves. To bring in a banned technology would therefore be at their own risk as the same could also be banned in this country which would eventually affect their standing and prestige in the international market. Approvals are also subject to Indian Laws including safety laws as also to compliance/clearance from the environmental and pollution control angle.

इलैक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा अर्जित लाभ

2726. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक लाभ कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये एकक अपने उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक एकक द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 8 उद्यम मुख्यतः इलैक्ट्रानिक उपकरणों का कारोबार कर रहे थे।

1. इंडियन टेलीफोन इंटस्ट्रीज लिमिटेड
2. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3. राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लि॰
4. इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
5. सेमी कंट्रेक्टर काम्पलैक्स लिमिटेड
6. सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
7. सी॰एम॰सी॰ लिमिटेड
8. इलैक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डिवेलप्मेंट कारपोरेशन

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन उद्यमों में से प्रत्येक द्वारा अर्जित किये गए लाभ / उठाई गई हानि तथा उनके द्वारा निर्यात से हुई आमदनी का ब्यौरा 22-3-1995 को सभा पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1993-94 के खंड I में विवरण संख्या 7 क/7ख तथा विवरण संख्या 24 में दिया गया है।